



संगठित अपराध और जॉर्जिया RICO अधिनियम

प्रलिस के लिये:

RICO अधिनियम, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999, संगठित अपराध

मेन्स के लिये:

भारत में संगठित अपराध से निपटने में चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर उनके 18 सहयोगियों के साथ जॉर्जिया रीको (रैकेटियर से प्रभावित और भ्रष्ट संगठन-Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।

- इन आरोपों में कथित तौर पर कई आपराधिक गतिविधियाँ जिनमें मुख्य रूप से जालसाजी, झूठे बयान देना, छद्म रूप से सरकारी अधिकारी के तौर पर स्वयं को प्रस्तुत करना, गवाहों को प्रभावित करना और साजिश रचना आदि शामिल हैं।
- रीको (RICO) अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (Maharashtra Control of Organised Crime Act-MCOCA), 1999 में कुछ समानताएँ हैं।

नोट: जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 अमेरिकी राज्यों में से एक है और यह दक्षिण-पूर्वी मुख्य भूमि में स्थित है।



जॉर्जिया रीको/RICO अधिनियम:

- वर्ष 1970 में रीको अधिनियम अमेरिकी संघीय कानून का हिस्सा बना।
- यह मूलतः संगठित अपराध, विशेष रूप से माफिया-संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिये अभिकल्पित है।
- संघीय कानून के प्रभावी होने के कुछ वर्षों के भीतर राज्यों ने अपना रीको कानून पारित करना शुरू किया।
- वर्ष 1980 में पारित जॉर्जिया का रीको अधिनियम, "रैकेटियरिंग गतिविधियों के पैटर्न" के माध्यम से अपराध संबंधी किसी "गतिविधि" में भाग लेना, उस पर नयित्रण अथवा ऐसा करने की साज्जिश करने को गैरकानूनी घोषित करता है।
- जॉर्जिया में रीको अधिनियम के तहत धोखाधड़ी के आरोप में दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष तक की जेल हो सकती है।
- कठोर दंड का प्रावधान इस अधिनियम के अनुप्रयोग की गंभीरता को रेखांकित करता है।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नयित्रण अधिनियम, 1999

- इसे महाराष्ट्र में संगठित आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिये पेश किया गया था।
- यह अधिनियम केवल महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य पर भी लागू होता है।
- इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध एक [संज्ञेय अपराध](#) है।
- इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध की सुनवाई केवल इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी।
- यह अधिनियम शक्तों के दुरुपयोग, कानून सम्मत कार्य करने में वफिल होने की स्थिति के लिये सख्त प्रावधान करता है, दोषी पाए गए व्यक्ति **दोषी पाए गए व्यक्ति** वर्ष तक का कारावास हो सकता है या उस पर **जुर्माना** लगाया जा सकता है।

संगठति अपराधः

- आर्थिक अथवा अन्य लाभ के इरादे से किसी गरीब या सडिकेट के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग कथि गए कृत्य को संगठति अपराधिक गतिविधियों के रूप में जाना जाता है।
- संगठति अपराध के प्रकारः संगठति गरीब अपराध, रैकेटियरिग, सडिकेट अपराध, तस्करी आदि।
- वे ऐसा कानून प्रवर्तन और वनियिमों में व्याप्त कमियों का लाभ उठाकर करते हैं।

संगठति अपराध और भारत की वधिकि व्यवस्थाः

- भारत में हमेशा ही किसी-न-किसी रूप में संगठति अपराध का अस्तित्व रहा है। हालाँकि कई सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कारकों तथा वजिज्ञान व प्रौद्योगिकि में हुई प्रगति के कारण आधुनिक समय में इसका उग्र रूप देखा गया है।
 - हालाँकि गिरामीण भारत भी संगठति अपराध से अछूता नहीं है, कति यह मूलतः एक शहरी परघटना है।
- भारत में राष्ट्रीय स्तर पर संगठति अपराध से नपिटने के लिये कोई वशिषिट कानून नहीं है। [राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियिम, 1980](#) तथा [स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधनियिम, 1985](#) जैसे मौजूदा कानून इस संदर्भ में अपर्याप्त हैं क्योंकि ये व्यक्तियों पर लागू होते हैं, न कि अपराधिक समूहों अथवा उद्यमों पर।
- कुछ राज्यों, जैसे कि गुजरात (गुजरात संगठति अपराध नयित्रण अधनियिम, 2015), कर्नाटक (कर्नाटक संगठति अपराध नयित्रण अधनियिम, 2000) और उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश संगठति अपराध नयित्रण अधनियिम, 2017) ने संगठति अपराध का मुकाबला करने के लिये अपने कानून बनाए हैं।
- भारत कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों (जनिका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर संगठति अपराध का उन्मूलन करना है) का भी भागीदार है।
 - जैसे:
 - [अंतरराष्ट्रीय संगठति अपराध के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र अभसिमय \(United Nations Convention against Transnational Organized Crime- UNTOC\)](#)।
 - [भ्रष्टाचार के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र अभसिमय \(United Nations Convention against Corruption- UNCAC\)](#)।
 - [ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय \(United Nations Office On Drug And Crime- UNODC\)](#)।
 - ये अभसिमय वभिन्न देशों के बीच सहयोग, पारस्परिक सहायता, कानून प्रवर्तन तथा सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

संगठति अपराध से नपिटने में चुनौतियाँः

- अपर्याप्त वधिकि संरचनाः संगठति अपराध समूहों और उद्यमों पर लागू कथि जा सकने योग्य समरपति कानून का अभाव।
- अपराध का प्रमाण प्राप्त करने में कठिनाईः पदानुक्रम उच्च नेतृत्व को प्रेरति करता है; गवाहों को अपनी जान का भय रहता है।
- संसाधन और प्रशिक्षण की कमीः संगठति अपराध की जाँच के लिये संसाधन, प्रशिक्षण और सुविधाओं की कमी।
- समन्वय की कमीः समन्वय और सूचना के आदान-प्रदान के लिये राष्ट्रीय एजेंसी का अभाव।
- आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही गठजोड़ः आपराधिक सडिकेट/समूह का राजनेताओं, नौकरशाहों तथा मीडिया के साथ संबंध होना बड़ी चुनौती उत्पन्न करता है।

आगे की राह

- रिको अधनियिम जैसे सफल अंतरराष्ट्रीय मॉडल से प्रेरति एक व्यापक राष्ट्रीय कानून वकिसति कथि जाना चाहिये।
- कानून प्रवर्तन के लिये वशिष प्रशिक्षण केंद्र स्थापति करना, संगठति अपराध से लड़ने हेतु आवश्यक तकनीकों का उपयोग।
- खुफिया जानकारी, साक्ष्य एकत्र करने और अंतर-एजेंसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रौद्योगिकि व बुनयादी ढाँचे हेतु वतित्त में वृद्धिकि जानी चाहिये।
- संगठति अपराध से प्रभावी ढंग से नपिटने के लिये राज्यों और केंद्रीय प्रवर्तन नकियों के बीच समन्वय स्थापति करने हेतु एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिये। अपराध पैटर्न और इसके प्रमुख क्षेत्रों की पहचान के लिये उन्नत डेटा एनालिटिक्स तथा कृत्रमि बुद्धिमिता का लाभ उठाते हुए नरिबाध सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा दया जा सकता है।
- आपराधिक-राजनीतिक गठजोड़ पर अंकुश लगाने के लिये सख्त नगिरानी तंत्र का क्रयान्वयन अत्यंत आवश्यक है। जवाबदेही सुनिश्चति करने व सत्ता के दुरुपयोग पर प्रतबिंध लगाने के लिये नागरिक समाज समूहों और मानवाधिकार संगठनों की सक्रयि भागीदारी को प्रोत्साहति कथि जाना महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

